नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 035
दि. 07.11.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

गुजरात में शहरी विकास की नई उड़ान: गिफ्ट और धोलेरा के बाद पीएम मोदी के राज्य में बनेंगे 5 सैटेलाइट टाउन

भूपेंद्र पटेल सरकार का बड़ा फैसला, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत और राजकोट के पास विकसित होंगी उपग्रह सिटी

(जीएनएस)।अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में शहरी विकास को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य में पांच बड़े शहरों — अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत और राजकोट — के पास पांच आधुनिक सैटेलाइट टाउन विकसित किए जाएंगे। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब पीएम मोदी द्वारा गुजरात में शहरीकरण की नींव रखे जाने के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। गुजरात सरकार का यह फैसला न सिर्फ शहरी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम है, बल्कि तेजी से बढ़ती आबादी और महानगरों पर बढ़ते दबाव को कम करने का भी प्रयास है। पहले से ही गिफ्ट सिटी (GIFT City) और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (Dholera SIR) जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अब ये पांच सैटेलाइट टाउन गुजरात के औद्योगिक और तकनीकी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं।

ये पांच सैटेलाइट टाउन होंगे विकसित

सरकार ने जिन पांच उपग्रह नगरों की घोषणा की है, वे हैं —

1. कलोल (गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र)
2. साणंद (अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र)
3. सावली (वडोदरा शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र)
4. बारडोली (सूरत शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र)
5. हीरासर (राजकोट शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र)

इन क्षेत्रों को 'मदर सिटीज' के साथ समन्वय में विकसित किया जाएगा ताकि इनकी आबादी, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं बड़े शहरों के बोझ को संतुलित कर सकें।

बेहतर शहरी जीवन और संतुलित विकास पर जोर

भूपेंद्र पटेल सरकार का कहना है कि यह योजना नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन, सस्ती

आवासीय सुविधाएं और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। इस पहल के तहत नगर नियोजन योजनाएं (TP Schemes) और मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। मेट्रो, बीआरटीएस, हरित राजमार्ग गलियारे और आधुनिक जल-निकासी प्रणालियों जैसी परियोजनाओं को शामिल करते हुए इन क्षेत्रों में समग्र बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा।

महानगरों पर दबाव घटेगा

सरकार का मानना है कि इन सैटेलाइट टाउन के विकसित होने से बड़े शहरों में जनसंख्या दबाव, यातायात जाम, महंगाई और जीवन-यापन की लागत में कमी आएगी। साथ ही नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उच्च स्तरीय समिति और प्रारंभिक निधि मंजूर

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की निगरानी और समन्वय के लिए गुजरात सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की है, जिसमें पर्यटन, खेल, शिक्षा, उद्योग, रोजगार, शहरी विकास, जल आपूर्ति और वित्त विभागों के सचिव शामिल होंगे। इस समिति को इन परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि भी मंजूर कर दी है।

गिफ्ट सिटी बनी मिसाल, अब नए शहरों पर नजर

गुजरात की गिफ्ट सिटी, जहां हाल ही में शराबबंदी आंशिक रूप से हटाई गई, पहले ही कई विदेशी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को आकर्षित कर चुकी है। वहीं धोलेरा को भारत के पहले "स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब" के रूप में तेजी से विकसित किया जा रहा है। अब राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ये नए सैटेलाइट टाउन भी निवेश और रोजगार के केंद्र बनें और गुजरात को एक वैश्विक अर्बन हब के रूप में स्थापित करें।

इस घोषणा के साथ ही गुजरात सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में राज्य का शहरी नक्शा पूरी तरह बदलने वाला है — जहां हर प्रमुख शहर के आसपास एक आधुनिक, योजनाबद्ध और हरित उपग्रह नगर विकसित होगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया गुजरात गढ़ेगा।

बीजापुर में मुठभेड़, तीन नक्सली ढेर; बड़े नक्सली नेताओं की तलाश जारी

(जीएनएस)।बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के रीमल्ल और अन्नारम के घने जंगलों में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर हो गए हैं। यह जानकारी गुरुवार को बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने पुष्टि की। डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया।

सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ में कई और नक्सलियों के मारे जाने की खबरें भी हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फायरिंग की आवाज इतनी तेज़ है कि यह आसपास के आबादी वाले इलाकों तक भी सुनाई दे रही है। पुलिस और सुरक्षा बल इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें मारे गए नक्सलियों की संख्या और उनकी पहचान अभियान के पूरा होने के बाद घोषित की जाएगी।

इस मुठभेड़ की पृष्ठभूमि यह है कि सुरक्षाबलों को बड़े नक्सली नेता पापा राव और केंद्रीय समिति सदस्य गणेश उइके की मौजूदगी की सूचना मिली थी। मुठभेड़ में घायल या मारे गए नक्सली इन बड़े नेताओं की सुरक्षा में लगे हुए थे। पुलिस अधिकारीयों ने बताया कि इस इलाके में दो दिन तक अभियान जारी रह सकता है और सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं।

बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य नक्सली हिंसा को जड़ से समाप्त करना है और जंगल में सक्रिय नक्सली तत्वों को पकड़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान न केवल सुरक्षा बलों की तत्परता को दर्शाता है, बल्कि यह स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इलाके में स्थायी शांति लाने की दिशा में भी अहम कदम है। स्थानीय अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के अभियान नक्सली नेटवर्क पर दबाव डालते हैं और इलाके में हिंसा की घटनाओं को कम करने में मददगार साबित होते हैं। वहीं, सुरक्षा बलों ने नागरिकों से अपील की है कि वे घने जंगलों और मुठभेड़ के इलाकों से दूर रहें और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें।

जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट यूनिटी का कब्जा, चारों पदों पर दर्ज की ऐतिहासिक जीत

(जीएनएस)।नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर लेफ्ट यूनिटी की मजबूत पकड़ को साबित कर दिया है। शनिवार को घोषित नतीजों में सभी चार प्रमुख पदों पर वामपंथी गठबंधन ने जीत दर्ज की। इस जीत के साथ जेएनयू परिसर में लेफ्ट यूनिटी ने लगातार अपना प्रभाव कायम रखा है। AISA (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) से लेफ्ट यूनिटी पैनल की उम्मीदवार अदिति मिश्रा ने अध्यक्ष पद (President) पर विजय हासिल की और जेएनयू छात्र राजनीति में एक नया चेहरा बनकर उभरीं। उपाध्यक्ष (Vice President) पद पर SFI (स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) की गोपिका बाबू ने जीत दर्ज की, जबकि जनरल सेक्रेटरी (General Secretary) के पद पर DSF (डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन) के सुनील यादव विजयी रहे। जॉइंट सेक्रेटरी (Joint Secretary) का पद AISA के दानिश अली ने अपने नाम किया।

जेएनयू में इस बार का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, लेकिन मतगणना के दौरान परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जैसे-जैसे परिणाम घोषित होते गए, लेफ्ट समर्थक छात्र संगठनों में जश्न की लहर दौड़ गई। परिसर में "लाल सलाम" के नारों से वातावरण गूंज उठा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेएनयू में लेफ्ट यूनिटी की यह जीत केवल छात्र राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैचारिक रूप से वामपंथी एकजुटता का प्रतीक भी है। पिछले कुछ वर्षों में जेएनयू छात्र राजनीति में कई नए संगठनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन लेफ्ट गठबंधन ने अपने संगठनात्मक ढांचे, वैचारिक स्पष्टता और छात्र हितों के मुद्दों पर केंद्रित राजनीति के बल पर फिर एक बार जीत हासिल की है।

अदिति मिश्रा ने जीत के बाद अपने संबोधन में कहा, "यह जीत छात्रों के अधिकारों, शिक्षा में समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। हम संघर्ष की उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, जिसने जेएनयू को विचारों की धरती बनाया है।"

उल्लेखनीय है कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव हमेशा से देशभर में छात्र राजनीति की दिशा तय करने वाले माने जाते हैं। लेफ्ट यूनिटी की यह जीत आने वाले समय में विश्वविद्यालय परिसर में नीतिगत बहसों और छात्र आंदोलनों को नई गति देने वाली मानी जा रही है।

मिशिगन यूनिवर्सिटी में चीनी शोधार्थियों पर जैविक तस्करी का आरोप, एफबीआई ने जांच शुरू की

(जीएनएस)।डेट्रॉइट (मिशिगन)। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में शोधरत तीन चीनी नागरिकों पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जैविक पदार्थों की तस्करी की साजिश रची। इस मामले में संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने तीनों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है।

अमेरिकी अटॉर्नी जेरोम एफ. गोरगन जूनियर ने बताया कि आरोपित शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला को ढाल बनाकर अवैध जैविक सामग्री अमेरिका लाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, "ये लोग न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन गए थे। हमें अपने संघीय सहयोगियों के सतर्क प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए।"

एफबीआई के अनुसार आरोपितों की पहचान शू बाई (28 वर्ष), फेंगफान झांग (27 वर्ष) और झियोंग झांग (30 वर्ष) के रूप में हुई है। ये सभी जे-1 वीजा धारक शोधार्थी हैं और मिशिगन विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध 'शॉन जू लैब' में कार्यरत थे।

जांच में सामने आया है कि वर्ष 2024 और 2025 के दौरान बाई और झांग ने गोल कृमियों (राउंडवर्म्स) से संबंधित जैविक पदार्थों के कई शिपमेंट प्राप्त किए, जिन्हें चीन के चेंगशुआन हान ने अमेरिका भेजा था। हान, जो वुहान के लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से पीएचडी कर रहे थे, जून 2025 में मिशिगन विश्वविद्यालय आए और बाद में तस्करी और झूठे बयानों के आरोप में देश से निष्कासित कर दिए गए। हान के निष्कासन के बाद विश्वविद्यालय ने 'शॉन जू लैब' में आंतरिक जांच शुरू की, जिससे इस पूरे तस्करी तंत्र का खुलासा हुआ। जांच के दौरान आरोपित शोधार्थियों ने अमेरिका से भागने की कोशिश की, लेकिन 10 अक्टूबर को संघीय एजेंटों के छापे के दौरान वे फरार हो गए। फिलहाल इनके अज्ञात ठिकानों पर छिपे होने की आशंका है। एफबीआई डेट्रॉइट फील्ड ऑफिस की विशेष एजेंट जेनिफर रनयान ने कहा कि एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "यह मामला इस बात का उदाहरण है कि विज्ञान और अनुसंधान की आड़ में की जा रही कोई भी अवैध गतिविधि कानून के शिकंजे से बच नहीं सकती।"

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला वैज्ञानिक अनुसंधान और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन की गंभीर चुनौती को उजागर करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अंतरराष्ट्रीय शोधार्थियों द्वारा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का दुरुपयोग न केवल कानून के तहत सजा का कारण बन सकता है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

17 लाख की इनामी महिला नक्सली कमला सोरी ने किया आत्मसमर्पण

(जीएनएस)।खैरागढ़/रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुरुवार को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। लंबे समय से फरार और 17 लाख रुपये के इनामी हार्डकोर महिला नक्सली कमला सोरी उर्फ उंगी उर्फ तरूणा (30) ने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत कमला सोरी को तुरंत 50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। कमला पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र (गोंदिया) और मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा कुल 17 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कमला सोरी सुकमा जिले के ग्राम अरलमपल्ली की निवासी हैं और वर्ष 2011 से प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से जुड़ी हुई थीं। वह माड़ डिवीजन के तहत एमएमसी (मध्य प्रदेश–महाराष्ट्र–छत्तीसगढ़) जोन में सक्रिय रही और नक्सली कमांडर रामदर की टीम में एक प्रमुख सदस्य के रूप में कार्य करती थीं।

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा ने बताया कि कमला सोरी का आत्मसमर्पण सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों के सतत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा, "कमला का यह निर्णय साबित करता है कि अब जंगलों में हिंसा और भय का रास्ता छोड़कर शांति और विकास की ओर लौटने की भावना बढ़ रही है। हमें उम्मीद है कि उसका यह कदम अन्य नक्सलियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा।"

पुलिस के अनुसार, कमला सोरी ने अपने लंबे समय के नक्सली जीवन और गतिविधियों को छोड़ते हुए शांति और सामान्य जीवन अपनाने का रास्ता चुना है। अधिकारियों का मानना है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा, पुनर्वास और रोजगार के अवसर देने से क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे आत्मसमर्पण न केवल सुरक्षा बलों के प्रयासों की सफलता को दर्शाते हैं, बल्कि यह यह भी साबित करते हैं कि जंगलों में हिंसा और भय का वातावरण धीरे-धीरे बदल रहा है और नक्सली संगठन धीरे-धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। कमला सोरी के इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि अन्य नक्सली भी सरकारी नीतियों और संवाद के माध्यम से शांति की ओर लौटेंगे।

हिजबुल्लाह ने इजराइल से बातचीत को ठुकराया, संघर्षविराम का पालन किया जाएगा

(जीएनएस)।बेरूत। लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह ने स्पष्ट किया है कि वह इजराइल के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेगा, चाहे वह सीधी हो या अप्रत्यक्ष। इसके बावजूद संगठन ने यह भी कहा कि वह अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में लागू किए गए संघर्षविराम का पालन करेगा ताकि आम नागरिकों को और पीड़ा न झेलनी पड़े। हिजबुल्लाह की यह घोषणा उस समय आई है जब पिछले वर्ष दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार इजराइल को 60 दिनों के भीतर लेबनानी क्षेत्र से हटना था, लेकिन इजरायली सेना अभी भी दक्षिणी लेबनान में अपनी चौकियों को बनाए हुए है।

हिजबुल्लाह की राजनीतिक परिषद ने बयान में कहा कि संघर्षविराम का सम्मान करना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, जिससे नागरिकों को और नुकसान न हो। लेकिन इजराइल से किसी भी प्रकार की संवाद प्रक्रिया देश की संप्रभुता पर चोट पहुँचाएगी। संगठन के प्रवक्ता ने टीवी पर कहा, "हम संघर्षविराम का पालन करेंगे ताकि हमारे लोगों को और कष्ट न हो, लेकिन इजराइल से बातचीत असंभव है। लेबनान झुकने वाला नहीं है।"

दोनों पक्षों के बीच जारी हिंसक संघर्ष में अब तक ढाई हजार से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 12 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में हुए संघर्षविराम समझौते के तहत हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर की ओर हटना था, जबकि इजराइल को अपनी सेनाओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा तक वापस ले जाना था।

इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ने कई बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया है। वहीं, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन का कहना है कि इजराइल अब भी पांच रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जा किए हुए है। हिजबुल्लाह को लगातार ईरान का समर्थन प्राप्त है और संगठन के नए प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि हिजबुल्लाह किसी भी हाल में अपने राष्ट्रीय सम्मान से समझौता नहीं करेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोषणा क्षेत्रीय तनाव को कम करने के बजाय और जटिल बना सकती है, क्योंकि लेबनान और इजराइल के बीच असंतोष की पुरानी जड़ें अब भी बनी हुई हैं। स्थानीय नागरिकों के लिए हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं और मानवाधिकार संगठनों ने हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों से संयम बरतने और नागरिकों को सुरक्षा देने की अपील की है। संघर्षविराम के बावजूद दक्षिणी लेबनान में सामान्य जीवन बहाल नहीं हो पाया है और हजारों विस्थापित लोग अभी भी अस्थायी शिविरों में जीवन यापन कर रहे हैं।

लेबनान और इजराइल के बीच यह गतिरोध एक बार फिर यह संकेत देता है कि क्षेत्रीय शांति की राह आसान नहीं है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और संघर्षविराम की स्थिति को स्थायी बनाने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के स्पष्ट रुख के कारण किसी भी तरह की वार्ता फिलहाल नामुमकिन नजर आ रही है।

संपादकीय

शिक्षा व शिक्षण की गुणवत्ता पर सवाल

निस्संदेह, शिक्षा मंत्रालय की वह रिपोर्ट परेशान करने वाली है, जिसमें बताया गया है कि बीते शिक्षा सत्र में देश के आठ हजार सरकारी स्कूलों में किसी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया। लेकिन विडंबना यह है कि इन स्कूलों में बीस हजार शिक्षक तैनात हैं। वहीं देश में हजारों स्कूल ऐसे हैं, जहां सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे सभी कक्षाएं चल रही हैं। वैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तीस विद्यार्थियों पर एक शिक्षक अनिवार्य रूप से होना चाहिए, लेकिन इसकी अनदेखी करके हर जगह विसंगतियां नजर आती हैं। यही वजह है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में आठ हजार स्कूलों में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि बिना दाखिले वाले स्कूलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है। यह संख्या 3,812 है, जो बेहद चौंकाने वाली बात है। स्थिति का दूसरा परेशान करने वाला तथ्य यह है कि इसी राज्य के बिना दाखिले वाले स्कूलों में बाकायदा करीब अठारह हजार शिक्षक तैनात हैं। कमोबेश तेलंगाना की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां 2,245 स्कूल जीरो एडमिशन वाले हैं तथा एक हजार से ज्यादा शिक्षक यहां तैनात हैं। वहीं भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, जिसका स्थान इस सूची में तीसरा है, वहां 463 स्कूलों में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। बाकायदा 223 शिक्षक इन जीरो एडमिशन वाले स्कूलों में तैनात हैं। वैसे चौंकाने वाली बात यह है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में इस बार के मुकाबले पांच हजार स्कूल अधिक ऐसे थे, जहां कोई विद्यार्थी दाखिल नहीं हुआ था। एक विसंगति यह भी है कि स्कूली शिक्षा राज्य सरकारों के अधीन होती है, अतः केंद्र सरकार का दखल इसमें नहीं होता। लेकिन राज्य सरकार व शिक्षा विभाग की नीतियों पर सवाल तो उठता ही है। इसके बावजूद केंद्रीय शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे शून्य दाखिले की परंपरा रोकने के लिये यथासंभव प्रयास करते रहें।

बहरहाल, यहां एक सवाल यह भी है कि बिना दाखिले वाले स्कूलों के शिक्षक छात्रों को स्कूल में लाने के व्यक्तिगत प्रयास क्यों नहीं करते? वैसे कुछ राज्यों के शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए हैं। जहां शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्रों की कम संख्या को देखते हुए उनका समायोजन अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में करके संतुलन साधने का प्रयास किया है। यहां हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ आदि के शिक्षा विभाग की सराहना करनी होगी, जहां एक भी स्कूल जीरो एडमिशन वाला नहीं था। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने राज्य भर के जीरो एडमिशन वाले 81 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया आरंभ की। इसका मानक यह होगा कि जहां पिछले लगातार तीन शैक्षणिक वर्षों में कोई छात्र दाखिल न हुआ हो। एक परेशान करने वाला आंकड़ा यह भी है कि देश के एक लाख स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक सभी कक्षाओं के छात्रों को पढ़ा रहा है, जिसमें करीब तैंतीस लाख छात्र अध्ययनरत हैं। जाहिर है वे छात्र क्या पढ़ रहे होंगे और उनका भविष्य क्या होने जा रहा है। यहां विचारणीय प्रश्न यह भी है कि छात्रों का सरकारी स्कूलों से मोहभंग क्यों हो रहा है? यह समाज विज्ञानियों के लिए अध्ययन का विषय होना चाहिए कि कम फीस व पर्याप्त शिक्षक व शिक्षण व्यवस्था के बावजूद छात्र इन स्कूलों में क्यों पढ़ना नहीं चाहते? यह विडंबना ही है कि जिन संस्थानों में नौकरी सुरक्षित और सुविधाएं पर्याप्त होती हैं, वहां कर्मचारी अपना बेहतर प्रदर्शन करते नजर नहीं आते। जबकि निजी स्कूलों में कम वेतन और कम सुविधाओं के बावजूद कर्मचारी जमकर मेहनत करते हैं। वहां शिक्षकों का खूब दोहन होता है लेकिन कक्षाएं छात्र-छात्राओं से भरी होती हैं। विडंबना यह भी कि अभिभावक ज्यादा फीस देकर भी संतुष्ट नजर आते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जिस दिन सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों व नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगेंगे, उस दिन सरकारी स्कूलों की दशा-दिशा सुधर जाएगी। फिलहाल देश में लाखों स्कूलों की स्थिति असंतोषजनक है और इस दिशा में गंभीर प्रयास की मांग की जाती है।

सार्ध शताब्दी के अवसर पर वंदे मातरम् के जयघोष से भारत भूमि को कोटि-कोटि वंदन...

"आज माननीय नरेन्द्रभाई के नेतृत्व में हमें विकास की जो नई ऊंचाइयां हासिल हो रही हैं, उसमें देश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक ही आकांक्षा है कि हमारी भारत माता हमेशा सुखदा और वरदा बनी रहे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के इस संकल्प-मार्ग पर हमें ऐसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो वंदे मातरम् के प्रत्येक शब्द को साकार रूप देकर एक नए युग की रचना कर रहे हैं।

भूपेंद्रभाई पटेल
लेखक
गुजरात के मुख्यमंत्री

हम आज देशभक्ति के एक अभूतपूर्व दौर में जी रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले जैसा जोश और देशभक्ति का वातावरण था, वैसा ही वातावरण हमारे राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्रभाई द्वारा प्रारम्भ किए गए 'आत्मनिर्भर भारत' और 'राष्ट्र प्रथम' जैसे प्रेरणादायी अभियानों के कारण आज फिर से निर्मित हो रहा है। इसी कड़ी में आज देशभक्ति के एक और स्मरण-पर्व को मनाने की घड़ी आ गई है। 1875 में रचित हमारा वंदे मातरम् गीत 150 वर्ष पूरे कर रहा है। यह गीत पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इस गीत ने देश की चेतना को जगाकर अपने इस सुदीर्घ गायन काल में मानों राष्ट्रभक्ति की प्राणवायु जैसी ऊर्जा उत्पन्न की।

इस गीत में अंतर्निहित उदात्त देशभक्ति और ऊर्जस्विता ने पूरे स्वाधीनता संग्राम में सतत जोश भरने का कार्य किया। इतिहासकारों का मत है कि चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, स्वदेशी आंदोलन हो या फिर सत्याग्रह की तैयारियाँ जहाँ भी वंदे मातरम् का स्वर उठता, वहाँ तत्काल देशभक्ति का ऊर्जावान वातावरण बन जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी अनेक नेता इस गीत की प्रत्येक पंक्ति को अपने जीवन से चरितार्थ करते रहे। महर्षि अरविन्द हों या भगतसिंह, सभी देशभक्त इस गीत के गूंजते स्वर में अपने जीवन की सर्वोच्च सार्थकता अनुभव करते थे।

इस राष्ट्र गीत की महिमा ही यह है कि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक, उतना ही ताजगीभरा और प्रेरणादायी प्रतीत होता है। आधुनिक युग के लोकनायक, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जब किसी सभा को संबोधित करने से पूर्व 'वंदे मातरम्' का जयघोष करवाते हैं, तब मानो पूरा सभामंडप देशभक्ति की एक नई लहर से भर उठता है। यह गीत भारतीयता की भावना का सजीव प्रतीक है। इस गीत के प्रत्येक शब्द से देश की सुजलाम् सुफलाम् धरा और भारत माता के प्रति भक्ति झलकती है। वंदे मातरम् का स्वर कानों में पड़ते ही हृदय में मातृ भक्ति का भाव जागृत होता है, मानो हम स्वयं भारत माता की आराधना कर रहे हों। इस गीत के शौर्य और पराक्रम की अनुभूति से तन-मन का प्रत्येक कण रोमांचित हो उठता है।

यह हमारा सौभाग्य है कि नरेन्द्रभाई ने जब से देश का नेतृत्व संभाला है, तब से मानो वंदे मातरम् के शब्दों ने नवजीवन पाकर एक बार पुनः अपनी दिव्य आभा बिखेर दी हो। ऐसा लगता है कि इस गीत में निहित देशभक्ति को माननीय नरेन्द्रभाई ने मानो साकार रूप दे दिया है। एक गीत के शब्दों को राष्ट्र के जीवन में कैसे उतारा जा सकता है इसके कई प्रेरणादायी उदाहरण उनके कार्य और परिश्रम के रूप में आज स्पष्ट दिखाई देते हैं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान 'आनंदमठ' उपन्यास में जिन संन्यासियों के संघर्ष का वर्णन था, आज नरेन्द्रभाई की तपस्या और त्याग उसी गीत की पंक्तियों को चरितार्थ करते प्रतीत होते हैं। वह ऐतिहासिक क्षण याद कीजिए जब कश्मीर के लाल चौक से नरेन्द्रभाई ने 'त्वं हि दुर्गा' की भावना पूरे देश में जागृत कर दी थी।

मा भारती को सच्चे हृदय से अर्पित वंदन ही 'वंदे मातरम्' है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह अमर गीत स्वातंत्र्य-संग्राम के दिनों में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम के उन्मेष का गगनभेदी घोष बनकर उभरा था। इसके प्रत्येक शब्द, और उन शब्दों से व्यक्त होने वाली प्रत्येक तेज-किरण ने स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में ऐसा प्रज्वलित संकल्प भरा कि वे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकने को उद्यत हो उठे। सन् 1875 में लिखे गए इस गीत के इस वर्ष 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यह तथ्य स्वयं रेखांकित करता है कि वंदे मातरम् मात्र एक गीत नहीं या शब्दों का कोई जटिल संयोजन नहीं बल्कि भारत-माता को समर्पित एक परम-पूज्य वंदन और एक करुणा से ओत-प्रोत नमन है।वंदे मातरम् गीत की सार्ध शताब्दी के अवसर पर मैं भी 7 करोड़ गुजरातियों की ओर से इस गीत को वंदन करते हुए मां भारती के प्रति कृतज्ञता और आदर व्यक्त करता हूं। वंदे मातरम् के 150वें वर्ष को एक विशेष, स्मरणीय वर्ष के रूप में मनाने का जो दूरदर्शी विजन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने देश को प्रदान किया है, वह उनके व्यक्तित्व में निहित राष्ट्र चेतना का ही उदात्त स्वरूप है। आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से आरम्भ हो रहे वंदे मातरम् गीत की 150वीं वर्षगाँठ के आयोजन में माँ भारती की संतानों के कल्याण का भाव अंतर्निहित है, ताकि वे गर्व से अपना मस्तक ऊंचा कर सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा नेतृत्व विरले ही देखने को मिलता है, जिसने अपने प्रत्येक कर्म, प्रत्येक संकल्प और प्रत्येक श्वास को राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर दिया हो। यह कहते हुए मुझे अपार गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी ऐसे ही विरल नेतृत्व की प्रथम पंक्ति में प्रतिष्ठित हैं। मोदीजी के प्रत्येक कार्य के केन्द्र में सदैव 'राष्ट्र प्रथम' की ही भावना रही है। महान क्रांतिवीर 'श्यामजी कृष्ण वर्मा' को सच्चे अर्थ में श्रद्धांजलि देने के लिए मांडवी में क्रांति तीर्थ की स्थापना करना हो या स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के महान बलिदान के प्रतीक 'भगवान बिरसा मुंडा' के महत्व को दुनिया के सामने लाने की बात हो या फिर राष्ट्रीय एकता के पर्याय सरदार वल्लभभाई पटेल को 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' और 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में स्मरणांजलि देने की बात हो, मोदी जी के प्रत्येक कार्य में हमें केवल एक ही भाव की अनुभूति होती है, और वह है 'वंदे मातरम्'।

मानो इस वंदे मातरम् गीत का यशगान करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी और विकास के नए युग का शुभारंभ किया। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने पंचशक्ति का उल्लेख करते हुए जल प्रबंधन जैसे विषयों को प्राथमिकता दी, क्योंकि वंदे मातरम् से उन्हें यह प्रेरणा मिली थी कि यह धरती शस्यश्यामला अर्थात् अन्नपूर्णा और समृद्धि से सम्पन्न भूमि है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कन्या शिक्षा और समग्र शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई, क्योंकि मोदी साहब जीवन भर 'वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्, अमलाम् अतुलाम्...' पंक्तियों को गुनगुनाते रहे हैं। इन पावन शब्दों में निहित अपार शक्ति और प्रेरणा से आरंभ हुई कन्या शिक्षा की यात्रा आज चंद्रमा पर स्थापित शिवशक्ति पॉइंट तक अपने विस्तार और उपलब्धि का संदेश देती है।

हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि देश के लिए दिन-रात निरंतर परिश्रम करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी इस वंदे मातरम् गीत को केवल गाते नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में धारण करते हुए जीते हैं। 'त्वं हि प्राणा शरीरे' की अनुभूति उनके प्रत्येक कार्य में दिखाई देती है, मानो उनकी हर सांस मातृभूमि को अर्पित एक जीवंत संकल्प-स्तुति बन गई हो। यही उनका आदर्श जीवन आज करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं, जब राष्ट्र के साहस और शौर्य को प्रदर्शित करने का समय आया तो कायर शत्रुओं को 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से यह दिखा दिया गया कि यह राष्ट्र ही हमारे लिए सर्वोच्च है और हमने वर्षों से इसे 'बहुबलधारिणीम् रिपुदलवारिणीम्' कहते हुए नमन किया है। यह देशभक्ति ही इस गीत की वो प्राण शक्ति है जिसने हमें दसों दिशाओं से साहस, संकल्प और ऊर्जा से अभिसिंचित किया है।

आज माननीय नरेन्द्रभाई के नेतृत्व में हमें विकास की जो नई ऊंचाइयां हासिल हो रही हैं, उसमें देश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक ही आकांक्षा है कि हमारी भारत माता हमेशा सुखदा और वरदा बनी रहे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के इस संकल्प-मार्ग पर हमें ऐसे दूरदर्शी प्रधानमंत्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो वंदे मातरम् के प्रत्येक शब्द को साकार रूप देकर एक नए युग की रचना कर रहे हैं। माँ जगतजननी और हमारी भारत माता हम सभी को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जब 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हों तब नरेन्द्रभाई जिस उत्साह, जिस ऊर्जा और जिस गर्व से हमसे जयघोष करवाते हैं हम भी उसी गौरव के साथ विश्व के समक्ष जयघोष कर सकें और गा सकें...'वंदे मातरम्...'

प्रेरणा

जब भगवान ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन को सिखाया विनम्रता का पाठ

द्वारका का राजमहल उस दिन अद्भुत आलोक से चमक रहा था। चारों ओर सुवर्ण स्तंभ, मणियों से जड़ी दीवारें और सुगंधित पुष्पों की महक वातावरण में ऐसी व्याप्त थी जैसे स्वयं वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया हो। सिंहासन पर श्रीकृष्ण विराजमान थे — श्याम वर्ण, मृदुल मुस्कान, नेत्रों में करुणा और अधरों पर अद्भुत सौम्यता। उनके साथ थीं उनकी प्रिय रानी सत्यभामा, जो अपनी अप्रतिम रूप-सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं। रानी के गले में मणिमालाएँ झिलमिला रही थीं, उनके वस्त्र सोने-सी चमक बिखेर रहे थे और उनका चेहरा ऐसे दमक रहा था जैसे स्वयं चंद्रमा धरती पर उतर आया हो।

बातों-बातों में सत्यभामा ने बड़ी सहजता से किंतु भीतर से गर्व भरे स्वर में कहा, "स्वामी, कहते हैं कि त्रेता युग में माता सीता अत्यंत सुंदर थीं। क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थीं?" यह प्रश्न उनके मुख से सहज ही निकला, पर श्रीकृष्ण के सर्वज्ञ हृदय ने जान लिया कि यह केवल जिज्ञासा नहीं, रूप पर उत्पन्न सूक्ष्म अहंकार का संकेत है। प्रभु मुस्कुराए — एक हल्की मुस्कान जो संसार के सारे रहस्यों को अपने भीतर समेटे रहती है।

उसी समय गरुड़, जो श्रीकृष्ण के वाहन और उनके परम भक्त हैं, अपने वेग पर गर्व महसूस कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि त्रिलोक में उनसे तेज कोई नहीं। और सुदर्शन चक्र, जो भगवान की परम शक्ति का प्रतीक है, अपने तेज और सामर्थ्य पर गर्वित था कि समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो उसे रोक सके। भगवान ने तीनों के मनोभाव जान लिए — सत्यभामा का रूप-अहंकार, गरुड़ का वेग-अहंकार और सुदर्शन का शक्ति-अहंकार। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, "समय आ गया है कि मैं इन्हें उनके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराऊं।"

श्रीकृष्ण ने योजना बनाई। उन्होंने गरुड़ को बुलाया और कहा, "गरुड़, तुम जाकर हनुमान जी को द्वारका ले आओ। मुझे उनसे भेंट करनी है।" गरुड़ गर्व से बोले, "जैसा आदेश, प्रभु।" उन्होंने सोचा कि वे तो सबसे तीव्र गति से उड़ने वाले हैं, पल भर में जाएंगे और हनुमान को ले आएंगे।

इस बीच श्रीकृष्ण ने स्वयं राम का रूप धारण किया। उनका रूप अब वैसा ही हो गया जैसा त्रेता युग में था — सादगी, सौम्यता, करुणा और मर्यादा का मूर्त रूप। उन्होंने सत्यभामा को आदेश दिया कि वे सीता का रूप धारण करें और सुदर्शन चक्र को कहा कि द्वार पर पहरा दें, कोई भीतर न आए।

गरुड़ अपने तीव्र पंखों से वायु को चीरते हुए हनुमान जी के पास पहुंचे और बोले, "वानरराज, प्रभु श्रीकृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ द्वारका।" हनुमान ने शांत स्वर में कहा, "आप जाइए, मैं आता हूं।" गरुड़ ने सोचा, "यह वृद्ध वानर कब द्वारका पहुंचेगा? मैं तो क्षणभर में वहां पहुंच जाऊंगा।" वे पंख फैलाकर द्वारका लौट आए।

पर जैसे ही उन्होंने द्वारका के आकाश में प्रवेश किया, देखा कि राजमहल के भीतर हनुमान जी पहले से ही बैठे हैं और प्रभु श्रीराम (यानी श्रीकृष्ण उनके राम रूप में) के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। गरुड़ की आंखें फैल गईं। उनके पंख जैसे स्थिर हो गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, "यह कैसे संभव है? मैं तो सीधा उड़कर आया, फिर भी यह मुझसे पहले कैसे पहुंच गए?" उसी क्षण उनका वेग-अहंकार टूट गया।

प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने गरुड़ की ओर देखा और बोले, "गरुड़, क्या अब भी कोई संदेह है कि भक्ति का वेग किसी भी पंख से तेज होता है?" गरुड़ ने सिर झुका लिया, लज्जा से उनका चेहरा झुक गया।

अब जब हनुमान जी राजमहल के द्वार की ओर बढ़े, तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, "रुको वानर, बिना अनुमति प्रवेश नहीं।" हनुमान ने सरलता से मुस्कुराते हुए कहा, "मैं अपने प्रभु के दर्शन को जा रहा हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता।" जब सुदर्शन ने बल प्रयोग किया, तब हनुमान ने उन्हें अपने मुख में समा लिया और भीतर प्रवेश कर गए।

प्रभु श्रीरामरूप में बैठे थे। उन्होंने पूछा, "हनुमान, तुम बिना अनुमति के भीतर कैसे आए?" हनुमान ने नम्र स्वर में कहा, "प्रभु, जिसने मुझे रोकने का प्रयत्न किया, उसे अपने साथ ही ले आया हूं।" और उन्होंने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला। सुदर्शन का तेज मंद हो गया, उनके मुख पर विनम्रता आ गई। उनका शक्ति-अहंकार भी उसी क्षण भस्म हो गया।

तभी हनुमान की दृष्टि सिंहासन पर बैठी सीता रूपिणी सत्यभामा पर पड़ी। वे गंभीर स्वर में बोले, "प्रभु, आज माता सीता के स्थान पर आपके साथ यह दासी क्यों बैठी हैं?" यह सुनते ही सत्यभामा का रूप-अहंकार जलकर राख हो गया। उनका हृदय कांप उठा, उन्होंने सिर झुका लिया। उन्हें समझ में आ गया कि बाहरी रूप-सौंदर्य केवल देह तक सीमित है, जबकि सीता का सौंदर्य उनके त्याग, भक्ति और पतिव्रता में निहित था — जो किसी भी अलंकार या आभूषण से कहीं ऊँचा था।

अब तीनों — सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन — प्रभु के चरणों में झुक गए। उनके मन से अहंकार का आवरण हट चुका था, और उसके स्थान पर केवल भक्ति, समर्पण और कृतज्ञता शेष थी।

श्रीकृष्ण ने तीनों को उठाया और स्नेह से बोले, "अहंकार वह पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच आ खड़ा होता है। जो अपनी गति, शक्ति या सौंदर्य पर गर्व करता है, वह यह भूल जाता है कि यह सब उसी परम सत्ता की देन है। जब मनुष्य अपने गुणों को 'मेरा' मानने लगता है, तभी उसका पतन आरंभ होता है। और जब वह यह जान लेता है कि सब कुछ उसी का है, तब उसका उद्धार होता है।"

यह कहकर भगवान ने तीनों को अपने आलिंगन में ले लिया। उस क्षण द्वारका में एक दिव्य आभा फैल गई। आकाश में वीणाएँ बज उठीं, गंधर्व गाने लगे, और हवा में फूल झरने लगे। सत्यभामा के नेत्रों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू अहंकार के नहीं, विनम्रता के थे।

इस प्रकार द्वारका की यह लीला संसार को यह सिखाने के लिए हुई कि ईश्वर अपने भक्तों के अहंकार को कभी नहीं सहन करते। चाहे वह रूप का हो, वेग का या शक्ति का — जब तक 'मैं' का भाव जीव में रहता है, तब तक वह ईश्वर से दूर रहता है। जब यह 'मैं' मिट जाता है, तब केवल 'तू' रह जाता है — और वहीं से भक्ति की पूर्णता आरंभ होती है।

यही है "अहंकार मर्दन" — जब प्रभु अपने प्रेम से भक्त के भीतर छिपे 'अहं' को तोड़ते हैं ताकि उसमें सच्चे समर्पण और शांति का प्रकाश खिल सके।

भारत में राज्य सरकारों के ऋणों में भारी वृद्धि इन राज्यों की अर्थव्यवस्था को ले डूबेगी

किसी भी नागरिक, वाणिज्यिक संस्थान, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा उत्पादक कार्यों के लिए बाजार से ऋण लेना केवल तब तक ही सही हैं जब तक बाजार से लिए गए ऋण से कम से कम उस स्तर तक आय का अर्जन हो कि इस ऋण के ब्याज एवं किश्त का भुगतान इस आय से आसानी से किया जा सके। परंतु, किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान द्वारा बाजार से ऋण यदि अनुत्पादक कार्य के लिए लिया जा रहा है तो इस ऋण के ब्याज एवं किश्त का भुगतान करना निश्चित ही मुश्किल कार्य हो सकता है। आज भारत के कुछ राज्यों की बजटीय स्थिति पर भारी दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इन राज्यों ने बाजार से भारी मात्रा में ऋण लिया हैं एवं इस ऋण का उपयोग अनुत्पादक कार्यों यथा बिजली के बिल माफ करना, नागरिकों के खातों में सीधे राशि जमा करना, मुफ्त पानी उपलब्ध कराना, कुछ पदार्थों पर सब्सिडी उपलब्ध कराना, आदि के लिए किया जा रहा है। इन राज्यों की स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि इन्हें ऋणों पर अदा किए जाने वाले ब्याज एवं किश्तों के भुगतान हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा हैं। यदि कुछ और वर्षों तक इन राज्यों की यही स्थिति बनी रही तो निश्चित ही यह राज्य दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाने वाले हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा भी बाजार से ऋण लेने की राशि में वृद्धि देखी जा रही है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार पर 1.74 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण बक़ाया था जो वर्ष 2025 में, लगभग दुगना होते हुए, बढ़कर 3.42 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया है और वर्ष 2029 तक इसके 4.89 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर तक हो जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद आज 4.19 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। इस प्रकार, भारत सरकार का ऋण, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 80 प्रतिशत के स्तर को पार कर गया है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की निर्भरता ऋण पर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जिसे देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। आज केंद्र सरकार पर 200 लाख करोड़ रुपए की राशि का ऋण बक़ाया है एवं समस्त राज्य सरकारों पर 82 लाख करोड़ रूपए का ऋण बकाया है, इस प्रकार केंद्र एवं राज्य सरकारों पर संयुक्त रूप से 282 लाख करोड़ रुपए का ऋण बक़ाया है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 81 प्रतिशत है। एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था ऋण के ऊपर विकसित की जा रही है। जबकि, भारतीय आर्थिक दर्शन ऋण पर निर्भरता को प्रोत्साहन नहीं देता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में, राजा के पास कोष में आधिक्य होने का वर्णन मिलता है। राजा के पास यदि ऋण के स्थान पर कोष का आधिक्य होगा तब वह राज्य अपने नागरिकों के कल्याण पर अधिक राशि खर्च करने की स्थिति में रहेगा। अर्थात, प्राचीन भारत में राज्यों का आधिक्य का बजट रहता था, उसी स्थिति में वे राज्य अपने नागरिकों के कल्याण के कार्यों को तेज गति से चलाने की स्थिति में रहते थे। राज्य का खजाना ही यदि खाली हो तो वे किस प्रकार से राज्य के नागरिकों के लिए भलाई के कार्य कर सकते हैं। आज की स्थिति, बिलकुल विपरीत दिखाई देती है और आज कुछ राज्य बाजार से ऋण लेकर भी नागरिकों को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध करा रहें हैं बगैर यह सोचे समझे कि आगे आने वाले समय में बाजार से लिए गए ऋण का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा।

आज भारत में कुछ राज्यों की स्थिति यह है कि वे अपनी कुल आय का 55 प्रतिशत भाग कर्मचारियों को वेतन, पेन्शन एवं उधार ली गई राशि पर ब्याज के भुगतान करने जैसी मदों पर खर्च कर रहे हैं। जबकि, विभिन्न राज्य अपनी आय को बढ़ा सकने की स्थिति में नहीं है। कुछ राज्य तो वर्ष भर में जिस आय की राशि का आंकलन करते हैं उसे प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं और बजटीय आय की राशि एवं वास्तविक आय की राशि में 11 प्रतिशत तक की कमी रहती है, जबकि इन राज्यों के खर्च नियमित रूप से बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार इन राज्यों का बजटीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह असहनीय स्थिति में पहुंच गया है।

आज राज्यों की कुल आय का 84 प्रतिशत भाग स्थिर मदों पर खर्च हो रहा है। प्रदेश को आगे बढ़ाने एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने के लिए कुछ राशि इन राज्यों के पास उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है। पूंजीगत खर्चों में लगातार हो रही कमी के चलते इन राज्यों में नए अस्पतालों का निर्माण, नए रोड का निर्माण नए स्कूल हेतु भवनों का निर्माण नहीं हो पा रहा हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे हैं। पंजाब में कुल आय का 76 प्रतिशत भाग कर्मचारियों के वेतन, पेन्शन एवं ऋण पर ब्याज अदा करने जैसी मदों पर खर्च हो रहा है इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 79 प्रतिशत एवं केरल में 71 प्रतिशत भाग उक्त मदों पर खर्च किया जा रहा है। साथ ही, कुछ राज्यों द्वारा अपनी कुल आय का भारी भरकम हिस्सा सब्सिडी जैसी मदों पर खर्च किया जा रहा है। जैसे, पंजाब द्वारा अपने बजटीय आय का 24 प्रतिशत भाग सब्सिडी पर खर्च किया जा रहा है। इसी प्रकार, हिमाचल प्रदेश द्वारा 5 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश द्वारा 15 प्रतिशत, तमिलनाडु द्वारा 12 प्रतिशत एवं राजस्थान द्वारा 13 प्रतिशत राशि सब्सिडी पर खर्च की जा रही है। पंजाब द्वारा तो अपने बजट की 100 प्रतिशत राशि (24 प्रतिशत सब्सिडी पर एवं 76 प्रतिशत राशि वेतन, पेन्शन एवं ब्याज पर खर्च की जा रही है) सामान्य मदों पर खर्च की जा रही है और पूंजीगत खर्चों के लिए शून्य राशि बचती है। विभिन्न राज्यों द्वारा पेन्शन की मद पर वर्ष 1980-81 में अपने राज्य की कुल आय का केवल 3.4 प्रतिशत की राशि का खर्च किया जा रहा था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 24.3 प्रतिशत हो गया। इसी कारण से भारत सरकार ने पेन्शन अदा करने के नियमों में परिवर्तन किया था। आज यदि पेन्शन की नीति को नहीं बदला गया होता तो इस मद पर होने वाला खर्च बढ़कर 30 प्रतिशत के आसपास पहुंच जाता। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के कई राज्यों ने अपने पूंजीगत खर्च को घटाया है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 के बीच राज्यों ने अपने पूंजीगत खर्च में 51 प्रतिशत तक की कमी की है। दिल्ली में 38 प्रतिशत, पंजाब में 40 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश में 41 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में 33 प्रतिशत से पूंजीगत खर्चों में कमी दर्ज हुई है। आज कई राज्य सरकारें सब्सिडी प्रदान करने की मद पर अपने खर्चों को लगातार बढ़ा रहीं हैं एवं पूंजीगत खर्चों को लगातार घटा रही हैं, जो उचित नीति नहीं कही जा सकती है।

अभियान

घर के मंदिर में गुरु और भगवान की फोटो साथ रखना सही या गलत – जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

घर का मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होता, यह हमारे घर का आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक केंद्र होता है। जहां मन, आत्मा और वातावरण — तीनों को शांति और शक्ति प्राप्त होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर से संबंधित हर नियम का गहरा अर्थ होता है, क्योंकि मंदिर का निर्माण, दिशा, और उसमें रखी वस्तुएं हमारे जीवन के हर पहलू पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालती हैं।

अक्सर लोग अपने घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों के साथ अपने पूज्य गुरुदेव की तस्वीर भी रखते हैं। यह प्रश्न अक्सर उठता है कि क्या गुरु और भगवान की तस्वीरें एक साथ रखना वास्तु दृष्टि से सही है या इससे कोई दोष उत्पन्न होता है। इस विषय में वास्तु शास्त्र और आध्यात्मिक सिद्धांत दोनों ही स्पष्ट और गहन संदेश देते हैं।

हिंदू धर्म में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना गया है। "गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥" इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा हैं, जो ज्ञान का सृजन करते हैं; गुरु ही विष्णु हैं, जो उस ज्ञान की रक्षा करते हैं; और गुरु ही महेश हैं, जो अज्ञान का नाश करते हैं। इस प्रकार गुरु स्वयं परम ब्रह्म के प्रतीक हैं। जब आप घर के मंदिर में गुरु की तस्वीर भगवान की मूर्ति या फोटो के साथ रखते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आप गुरु को उसी श्रद्धा और सम्मान से पूजते हैं, जिस भाव से भगवान को पूजते हैं।

वास्तु शास्त्र कहता है कि मंदिर में गुरु और भगवान की तस्वीरें साथ रखना पूर्णतया शुभ और सकारात्मक माना जाता है। इसका कारण यह है कि मंदिर ज्ञान और भक्ति — दोनों का संगम होता है। गुरु ज्ञान का प्रतीक हैं और भगवान भक्ति का। जब दोनों की उपस्थिति एक ही स्थान पर होती है, तो घर में आध्यात्मिक संतुलन उत्पन्न होता है। इससे वातावरण में शुद्धता, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गुरु वह प्रकाश हैं जो हमें अंधकार से निकालकर ईश्वर के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। जैसे दीपक सूर्य की ज्योति का विस्तार है, वैसे ही गुरु ईश्वर की करुणा का विस्तार हैं। इसलिए गुरु की तस्वीर मंदिर में रखना न केवल उचित बल्कि अत्यंत शुभ माना जाता है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है —

घर के मंदिर में भगवान की तस्वीर या मूर्ति हमेशा गुरु की तस्वीर से थोड़ा ऊपर रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि गुरु का महत्व कम है, बल्कि यह इस भाव का प्रतीक है कि गुरु स्वयं हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान परम सत्ता हैं और गुरु उनके दूत — इस व्यवस्था को सम्मान देने के लिए ऐसा स्थान निर्धारण किया जाता है।

दूसरा नियम यह है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति के दाहिनी ओर गुरु की तस्वीर रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दाहिनी दिशा (दक्षिण या दक्षिण-पूर्व) पुरुष तत्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। इससे घर के व्यक्ति का मान-सम्मान, कीर्ति और आत्मबल बढ़ता है।

यह भी ध्यान रखें कि गुरु या भगवान की तस्वीरें किसी भी हालत में पैरों की सीध में, बेडरूम के भीतर, या ऐसी जगह न रखें जहाँ पैर उनकी ओर हों या अपवित्रता का भाव उत्पन्न हो। मंदिर हमेशा घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में होना चाहिए, और वहाँ स्वच्छता, सुगंध और पवित्रता बनी रहनी चाहिए।

जब गुरु और भगवान दोनों की तस्वीरें एक साथ होती हैं, तो यह घर में ऊर्जा का अद्भुत संगम बनाती हैं। गुरु की उपस्थिति मानसिक शांति, विवेक और दिशा प्रदान करती है, जबकि भगवान की उपस्थिति विश्वास, प्रेम और भक्ति उत्पन्न करती है। दोनों मिलकर व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं और जीवन की कठिनाइयों में सहजता से राह दिखाते हैं।

शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जहाँ गुरु और भगवान दोनों की उपासना होती है, वहाँ अज्ञान, भय और नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता। उस घर में रहने वाले व्यक्ति को अपने निर्णयों में स्पष्टता, अपने कर्मों में श्रद्धा और अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है।

इस प्रकार घर के मंदिर में गुरु और भगवान की तस्वीरें एक साथ रखना न केवल सही है बल्कि अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। बस यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यवस्था, दिशा और शुद्धता के नियमों का पालन किया जाए। जब भक्त अपने गुरु को भगवान के समान सम्मान देता है और भगवान को गुरु के रूप में अनुभव करता है, तब वह अपने जीवन में भक्ति, ज्ञान और मोक्ष — तीनों की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है।

इसलिए कहा गया है —

"गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूँ पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय॥"

अर्थात जब गुरु और भगवान दोनों सामने हों, तो पहले किसे प्रणाम करूं? क्योंकि गुरु ही वह हैं, जिन्होंने मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया। यही वह भाव है जो घर के मंदिर में गुरु और भगवान की एक साथ उपस्थिति को न केवल उचित बल्कि परम शुभ बना देता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

प्यार में धोखा, बदले की आग और झूठे ईमेल — जब एक साइबर एक्सपर्ट ने ही कर दी पुलिस की नींद हराम

(जीएनएस) ।बेंगलुरु। यह कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है — प्यार, धोखा, बदला और एक ऐसा डिजिटल खेल, जिसने देश की कई पुलिस एजेंसियों को उलझा दिया। गुजरात और कर्नाटक ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में एक साथ स्कूलों को बम धमाके की ईमेल धमकी मिली। सैकड़ों बच्चों को स्कूल से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, पुलिस-डॉग स्क्वॉड से लेकर बम निरोधक दस्ते तक हरकत में आ गए। पर जब जांच आगे बढ़ी, तो जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया — इन सबके पीछे एक महिला थी, वह भी कोई आम नहीं बल्कि एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ।

यह महिला थी रेने जोशिल्डा, उम्र मात्र 30 वर्ष, मूल रूप से गुजरात की रहने वाली और पेशे से एक रोबोटिक इंजीनियर। इतना ही नहीं, वह एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी डेलॉयट में सीनियर एडवाइजर के पद पर कार्यरत थी। उसके पास तकनीकी ज्ञान, कोडिंग स्किल्स और साइबर सुरक्षा की गहरी समझ थी — लेकिन दिल टूटने के बाद उसने अपने इसी ज्ञान को अपराध में बदल दिया।

रेने ने अपने पूर्व प्रेमी प्रभाकर से बदला लेने के लिए ऐसा डिजिटल जाल बुना, जिसने पुलिस से लेकर पूरे साइबर विभाग को चकरा दिया। प्रभाकर से उसका रिश्ता कई साल तक चला, लेकिन फिर दोनों में झगड़ा हुआ और प्रभाकर ने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। रेने इस रिश्ते को भुला नहीं पाई। उसके मन में प्रतिशोध की आग जलती रही। उसने सोचा कि अगर प्रभाकर को किसी गंभीर अपराध में फंसा दिया जाए, तो उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी और शायद वह वापस उसके पास लौट आए। इसी जुनून में रेने ने प्रभाकर के नाम से कई फर्जी ईमेल आईडी और वॉट्सएप अकाउंट बनाए। वीपीएन (Virtual Private Network) का इस्तेमाल करके उसने अपनी लोकेशन छिपाई और "गेट कोड" नामक ऐप के ज़रिए वर्चुअल मोबाइल नंबर हासिल किए। इसके बाद उसने देशभर के स्कूलों को बम धमकी वाले ईमेल भेजे।

ईमेल्स का कंटेंट ऐसा था कि किसी भी पुलिस एजेंसी को सतर्क होना ही था — "हम आपके स्कूल में बम रख चुके हैं, बच्चे मरेंगे, कोई नहीं बचेगा।" इस मेल के बाद अफरा-तफरी मच गई। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना — कुल 11 राज्यों के दर्जनों स्कूलों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया।

पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो शुरुआती स्तर पर सब कुछ तकनीकी रूप से इतना परफेक्ट छिपाया गया था कि असली अपराधी तक पहुंचना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन धीरे-धीरे जब साइबर एक्सपर्ट्स ने ईमेल सर्वर, VPN लॉग और गेट कोड एप के डेटा का विश्लेषण किया, तब धागा रेने जोशिल्डा तक पहुंचा।

बेंगलुरु के सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) और गुजरात की साइबर पुलिस ने जब संयुक्त जांच की, तो पता चला कि रेने ने करीब छह से सात वॉट्सएप अकाउंट, कई ईमेल आईडी और फर्जी डिजिटल पहचानें बनाकर यह साजिश रची थी। उसके लैपटॉप और मोबाइल से सैकड़ों ईमेल, चैट्स और VPN कनेक्शन की हिस्ट्री बरामद हुई।

सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि रेने ने अपने एक ईमेल आईडी का नाम रखा था — "divijpprabhakaralaksmi@gmail.com", ताकि ऐसा लगे कि मेल प्रभाकर ने खुद भेजे हैं। उसने बेंगलुरु के सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट, कलासीपल्या और उत्तरी क्षेत्र के निजी स्कूलों को टारगेट किया। कुछ ईमेल्स में उसने लिखा था कि "आज स्कूल उड़ जाएगा, कोई नहीं बचेगा।"

जांच में यह भी सामने आया कि उसने अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे का ज़िक्र करते हुए एक फर्जी मेल भेजा था, जिसमें उसने खुद को "उस दुर्घटना का जिम्मेदार" बताया — ताकि देशभर में उसके ईमेल्स को "आतंकी धमकी" माना जाए और पुलिस प्रभाकर को तुरंत पकड़ ले।

जब पुलिस ने आखिरकार रेने को गिरफ्तार किया, तो वह शांत और संयमित दिख रही थी। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने यह सब अपने एकतरफा प्यार और प्रतिशोध के कारण किया। उसका कहना था — "वह मुझे छोड़कर किसी और की हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि वह खुश रहे। मैंने बस उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी चाही।"

गुजरात पुलिस ने पहले उसे गिरफ्तार किया और बाद में बेंगलुरु पुलिस ने उसे 28 अक्टूबर को ट्रांज़िट रिमांड पर लिया। उससे लंबी पूछताछ की गई, फिर उसे वापस गुजरात भेज दिया गया, जहां वह फिलहाल जेल में बंद है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जोशिल्डा अत्यधिक बुद्धिमान है, लेकिन उसका दिमाग अब जुनून से ग्रस्त है। उसके खिलाफ अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351 (आपराधिक धमकी) और आईटी एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है — कि तकनीक की शक्ति जब भावनाओं से टकराती है, तो इंसान इंसान नहीं, एक डिजिटल राक्षस बन सकता है। प्यार में हारने वाली यह महिला साबित करती है कि दिल का ज़हर, जब दिमाग में उतरता है, तो सिर्फ रिश्ते नहीं, समाज भी कांप उठता है।

रेप और धोखाधड़ी के मामले में फरार AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस, पंजाब पुलिस ने जारी किया अलर्ट

(जीएनएस) ।लुधियाना। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर सनसनी फैल गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पर लगे रेप, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के गंभीर आरोपों के बाद वह अब फरार हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और राज्य भर में उनकी तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस को शक है कि विधायक किसी भी वक्त देश छोड़कर भाग सकते हैं।

पठानमाजरा, जो सनौर विधानसभा क्षेत्र से AAP विधायक हैं, पर यह मामला जीरकपुर की एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में 2021 में शादी भी की, जबकि वह पहले से ही विवाहित था। शिकायत में कहा गया कि विधायक ने लगातार उसका यौन शोषण किया, उसे धमकियां दीं, और कई बार अश्लील सामग्री भेजी।

महिला की शिकायत पर 1 सितंबर को सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें पठानमाजरा के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया गया। इसके बाद विधायक ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी, लेकिन स्थानीय अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत रद्द होने के बाद से ही वह 2 सितंबर से फरार हैं।

पुलिस ने अब विधायक के देश से बाहर भागने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया है। पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, ताकि हवाई अड्डों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर उनकी निगरानी की जा सके। साथ ही सनौर विधानसभा क्षेत्र, उनके सरकारी आवास और बस स्टैंड पर भी पठानमाजरा के पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिनमें लोगों से अपील की गई है कि अगर वह कहीं दिखें, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।

थाना सिविल लाइंस के प्रभारी गुरमीत सिंह ने बताया कि विधायक की गिरफ्तारी के लिए कई ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और जनता की मदद से विधायक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले ने आम आदमी पार्टी को असहज स्थिति में ला दिया है, क्योंकि पार्टी के कई विधायक पहले भी विवादों में रहे हैं। फिलहाल पठानमाजरा मामले में सरकार और पुलिस दोनों ही कठोर रुख अपनाने की बात कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के अनुसार, यदि विधायक ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो अदालत में घोषित अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा है कि क्या यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल छिपा है। मगर जो भी हो, फिलहाल पंजाब पुलिस का सारा ध्यान फरार विधायक को पकड़ने पर केंद्रित है, ताकि आरोपों की सच्चाई अदालत के सामने आ सके।

दिल्ली की हवा में जहर, ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार 27 इलाके रेड जोन में पहुंचे, AQI 300 के पार

(जीएनएस) ।नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम तो करवट ले रहा है, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। हवा की दिशा बदलने और तापमान गिरने के बावजूद प्रदूषण में कोई खास कमी नहीं आई है। ठंडी हवाओं के साथ अब दिल्लीवालों को प्रदूषण का भी डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। आज भी शहर के 27 से ज़्यादा इलाके रेड ज़ोन में हैं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाका बवाना रहा, जहां AQI 366 तक पहुंच गया।

सुबह के समय हल्की ठंडक और धुंध ने राजधानी को अपनी चपेट में ले लिया। सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों की मात्रा कम नहीं हो रही। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली का ओवरऑल AQI 310 दर्ज हुआ है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। दिल्ली के जिन 27 इलाकों में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है, उनमें अलीपुर का AQI 313, आनंद विहार 324, अशोक विहार 319, बवाना 366, बुराड़ी क्रॉसिंग 343, चांदनी चौक 346, मथुरा रोड 331, करणी सिंह शूटिंग रेंज 321, द्वारका सेक्टर-8 313, आईटीओ 334, जहांगीरपुरी 328, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 302, मंदिर मार्ग 303, मुंडका 336, नरेला 333, नेहरू नगर 334, नॉर्थ कैंपस 313, ओखला फेज-2 306, पटपड़गंज 309, पंजाबी बाग 342, पूसा 332, आरके पुरम 326, रोहिणी 336, सिरीफोर्ट 333, सोनिया विहार 322, विवेक विहार 324 और वजीरपुर 337 रहा। हालांकि कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 से नीचे दर्ज किया गया है, लेकिन वे भी 'खराब' श्रेणी में आते हैं। इनमें डीटीयू का AQI 271, आया नगर 264, दिलशाद गार्डन 248, लोधी रोड 218, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 293, नजफगढ़ 271, शादीपुर 260 और अरबिंदो मार्ग 284 शामिल हैं। इन जगहों पर हवा में धूल और विषैले कणों की मात्रा सामान्य से कई गुना ज़्यादा है।

दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों — नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम — में भी हालात गंभीर हैं। ग्रेटर नोएडा का AQI 248, नोएडा का 272 और गुरुग्राम का 245 दर्ज किया गया। हवा की गुणवत्ता में सुधार की कोई संभावना अगले कुछ दिनों में नहीं दिख रही है।

इस बीच दिल्ली का तापमान लगातार गिर रहा है। आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह-शाम की ठंड अब बढ़ने लगी है, जिससे प्रदूषण का असर और घातक हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे तापमान घटेगा, हवा की गति धीमी होगी और प्रदूषण के कण ज़मीन के पास फंसते जाएंगे।

प्रदूषण और ठंड के इस मिश्रण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अस्पतालों में सांस की तकलीफ, आंखों में जलन, सर्दी-जुकाम और गले में खराश की शिकायतों वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे सुबह और शाम के समय घर से बाहर निकलने से बचें, बाहर जाएं तो मास्क पहनना न भूलें, और घर के अंदर एयर प्यूरीफायर या पौधों का इस्तेमाल करें।

दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत कई पाबंदियां लागू हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने, निर्माण कार्य और वाहनों के उत्सर्जन पर सख्त रोक नहीं लगाई जाती, तब तक राजधानी की हवा में यह जहर बना रहेगा।

दिल्लीवासी इस वक्त ठंड से ठिठुरने के साथ-साथ प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि राजधानी में फिलहाल 'सांस लेना' ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है।

असारवा-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए असारवा-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित करने निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 01906/01905 असारवा-कानपुर सेंट्रल-असारवा साप्ताहिक स्पेशल (6 फेरे)

ट्रेन संख्या 01906 असारवा-कानपुर सेंट्रल स्पेशल जिसे 4 नवंबर 2025 तक अधिसूचित किया गया था अब उसे 25 नवंबर 2025 तक विस्तारित किया गया है। इस तरह ट्रेन संख्या 01905 कानपुर सेंट्रल-असारवा स्पेशल जिसे 3 नवंबर 2025 तक अधिसूचित किया गया था अब उसे 24 नवंबर 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 01906 के विस्तारित फेरों की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का वडोदरा में आयोजन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के रेल सुरक्षा बल द्वारा वडोदरा के वाघोडिया स्थित स्पोर्ट्स परिसर में 41 वीं अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का 12 नवंबर, 2025 तक आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप का शुभारम्भ स्पोर्ट्स परिसर में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि एवं वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के कर कमलों द्वारा किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि एवं वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी तथा खिलाड़ियों से खेल को खेल भावना से खेलने एवं अनुशासन तथा सम्मान के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आवाहन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को रेल सुरक्षा बल की गरिमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया।

खिलाड़ीओं के प्रति अपने स्वागत सम्बोधन में उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष एवं इस प्रतियोगिता की विजेता टीम को ऑल इंडिया पुलिस मीट बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने का गौरव प्राप्त होगा, जो पश्चिम बंगाल में आयोजित की जाएगी।

प्रतियोगिता के आर्गनाइजिंग सेकेट्री एवं मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री फ्रांसिस लोबो ने इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी पर ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए बताया कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मनोबल और टीम भावना को भी मजबूत करता है। उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष की प्रतियोगिता में 16 क्षेत्रीय रेलवे से कुल 135 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें 8 गैजेटेड ऑफीसर भी है तथा 21 महिला खिलाड़ी एवं 106 अन्य खिलाड़ी सम्मलित है। यह प्रतियोगिता 12 नवंबर तक आयोजित की जा रही है।

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, जनजातीय गौरव वर्ष का उत्सव

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल शुक्रवार को अंबाजी से 'जनजातीय गौरव यात्रा' का शुभारंभ कराएंगे
- 14 आदिजाति जिलों सहित राज्यभर में जन जागृति तथा आदिजाति गौरव के संदेश के साथ जनजातीय गौरव यात्रा का राज्य सरकार का आयोजन
- 7 से 13 नवंबर तक अंबाजी से एकता नगर तथा उमरगाम से एकता नगर रूट पर यात्रा भ्रमण करेगी
- रूट पर स्थित गाँवों में रथयात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य जाँच शिविर, सेवा सेतु, सामूहिक स्वच्छता सहित सेवाभावी कार्यक्रम जन भागीदारी से आयोजित होंगे
- अंबाजी में मुख्यमंत्री द्वारा यात्रा के शुभारंभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी सहित राज्य मंत्री उपस्थित रहेंगे

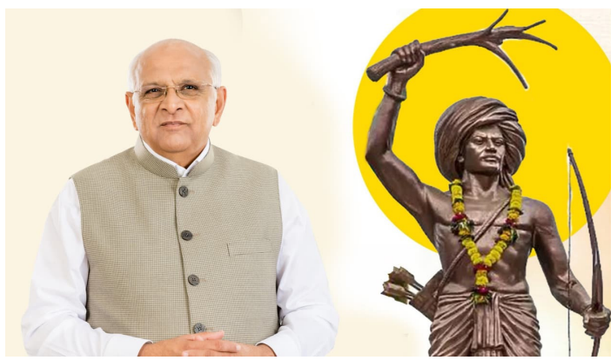

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल 7 नवंबर शुक्रवार को आद्यशक्ति धाम अंबाजी से 'जनजातीय गौरव यात्रा' का शुभारंभ कराएंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से इस वर्ष आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। आज की पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा मुंडा की अगुवाई में आदिजातियों के ऐतिहासिक योगदान को जाने-समझे तथा उससे राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा प्राप्त करे; इस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस वर्ष को 'जनजातीय गौरव वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में 'जनजातीय गौरव वर्ष उत्सव' अंतर्गत आयोजित हो रही जनजातीय गौरव यात्रा के अंबाजी से शुभारंभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी सहित राज्य मंत्री सर्वश्री पी. सी. बरंडा, कमलेशभाई पटेल, प्रवीणभाई माली तथा स्वरूपजी ठाकोर उपस्थित रहेंगे।

यह यात्रा दो स्थानों उत्तर गुजरात के आदिजाति क्षेत्र अंबाजी तथा दक्षिण गुजरात के महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित उमरगाम से 7 से 13 नवंबर तक आयोजित होगी। इस दौरान यह यात्रा 14 आदिजाति जिलों सहित राज्य के विभिन्न जिलों में जन जागृति तथा आदिजाति गौरव के संदेश को जन-जन तक प्रसारित करेगी।

यात्रा के दौरान जनजातीय गौरव रथ जिन गाँवों में जाएगा, वहाँ लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा तथा रात्रि विराम स्थलों पर भगवान बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र पर आधारित नाटक मंचन, निदर्शन तथा केन्द्र-राज्य सरकार की योजनागत जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। इतना ही नहीं; रथयात्रा के माध्यम से उसके रूट पर स्थित गाँवों में स्वास्थ्य जाँच शिविर, सेवा सेतु, सामूहिक स्वच्छता सहित सेवाभावी कार्यक्रम जन भागीदारी से आयोजित होंगे। बच्चे, युवा तथा समग्र समाज भगवान बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र से परिचित हों; ऐसे कार्यक्रम भी इस यात्रा के दौरान आयोजित होंगे।

इसके अलावा; भगवान बिरसा मुंडा के राष्ट्र निर्माण के लिए दिए गए योगदान पर चित्रकला तथा वक्तव्य प्रतियोगिता, नाटक-भवाई तथा उनके जीवन पर व्याख्यान, फिल्म प्रदर्शन भी राज्य सरकार के विभागों द्वारा आयोजित होने वाले हैं।

14 आदिजाति जिलों के अलावा 20 जिलों में भी 13 से 15 नवंबर के दौरान जनजातीय गौरव वर्ष उत्सव के विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरक उपस्थिति में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का राष्ट्रीय स्तर का समारोह डेडियापाडा में देवमोगरा माताजी के सान्निध्य में आयोजित होगा। राज्य सरकार ने 'विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात' का लक्ष्य हासिल करने के लिए दूरदराजी व सुदूरवर्ती गाँवों के प्रत्येक आदिजाति बांधवो को विकास की राह में अग्रसर रखने की मंशा रखी है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह जनजातीय गौरव रथयात्रा आदिजातियों को विकास की मुख्य धारा में लाकर राष्ट्र निर्माण में जोड़ने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार करने वाली इस रथयात्रा से जनजातीय गौरव वर्ष के उत्सव को भव्य बनाने तथा भगवान बिरसा मुंडा द्वारा दिए गए 'हमारा देश, हमारा राज' के नारे को आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत के निर्माण से चरितार्थ करने का भी आह्वान किया।

23 साल बाद आया फैसला: अहमदाबाद कोर्ट ने गुजरात दंगे के तीन आरोपियों को किया बरी, सुनवाई के दौरान गायब हुआ 'सबूत वाला वीडियो'

(जीएनएस)।अहमदाबाद। गुजरात दंगों से जुड़ा एक 23 साल पुराना मामला आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंच गया। अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को तीन आरोपियों को बरी कर दिया — जिन पर 2002 के दंगों के दौरान हथियारों के साथ हिंसा में शामिल होने का आरोप था। इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मुकदमे के दौरान वह वीडियो सबूत, जिसे इस केस की रीढ़ माना जा रहा था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह वीडियो वीडियोग्राफर सतीश दलवाड़ी ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें कथित तौर पर आरोपी लोगों को एके-47 और रिवॉल्वर जैसे हथियारों के साथ हिंसा करते हुए देखा जा सकता था। यह वीडियो 2002 में दरियापुर इलाके में हुए दंगों से जुड़ा था। लेकिन अदालत में यह टेप कभी पेश नहीं किया गया। बाद में वीडियोग्राफर ने भी अपना बयान पलट दिया, जिससे पूरा मामला अभियोजन के पक्ष से कमजोर पड़ गया। यह केस 14 अप्रैल 2002 को दरियापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज दो एफआईआर से जुड़ा था। वीडियोग्राफर सतीश, जो उस वक्त क्षेत्र की शांति समिति का सदस्य था, को तत्कालीन पुलिस निरीक्षक आर.एच. राठौड़ ने सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को कैमरे में कैद करने को कहा था। सतीश ने दावा किया था कि उसने आलमगिरी शेख, हनीफ शेख, इम्तियाज शेख, रऊफमिया सैयद और अन्य को हिंसा में शामिल देखा था। इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर आर्म्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। हालांकि, बीते दो दशकों में यह मुकदमा लगातार कमजोर होता चला गया। 23 साल की कानूनी प्रक्रिया में न केवल गवाहों ने अपने बयान बदले, बल्कि कुछ गवाहों और एक अभियुक्त की भी मौत हो गई। जांच अधिकारी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक गवाह ने अदालत को बताया कि उससे चाय की दुकान पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे, जबकि शिकायतकर्ता सतीश दलवाड़ी ने कहा कि उसे यह तक याद नहीं कि उसने क्या रिकॉर्ड किया था।

जब सुनवाई अपने अंतिम चरण में पहुंची, तो अदालत ने पाया कि वीडियो कैसेट कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ, और न ही किसी स्वतंत्र स्रोत से यह साबित हुआ कि आरोपियों के पास वास्तव में हथियार थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, और न ही ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी सबूत पेश किया गया जिससे यह साबित हो सके कि कथित अपराध के समय अभियुक्तों के पास बंदूकें थीं।

इस तरह अहमदाबाद कोर्ट ने 23 साल पुराने इस केस में तीनों आरोपियों को "सबूतों के अभाव में बरी" कर दिया।

यह फैसला एक बार फिर उस लंबे सिलसिले की याद दिलाता है जिसमें 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े कई पुराने मामले सबूतों की कमी, गवाहों के पलटने और मुकदमों के खिंच जाने के कारण कमजोर पड़ते गए। अदालत के इस फैसले ने न्यायिक प्रक्रिया में सबूतों के संरक्षण और गवाहों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

ईडी ने धनशोधन केस में फिर बुलाया अनिल अंबानी, दो दिन पहले ही 7,500 करोड़ की संपत्ति जब्त

(जीएनएस) ।नई दिल्ली। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के घेरे में आ गए हैं। ईडी ने उन्हें 14 नवंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। यह समन उस वक्त आया है जब एजेंसी ने हाल ही में उनकी कंपनियों की 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से जुड़े एक कथित बैंक लोन धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में की गई है। ईडी के सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने अगस्त में भी 66 वर्षीय उद्योगपति से पूछताछ की थी, लेकिन जांच में मिले नए वित्तीय दस्तावेज़ों और विदेशी ट्रांज़ैक्शनों की जानकारी के बाद अब उन्हें दोबारा तलब किया गया है।

यह मामला कई बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा दिए गए हज़ारों करोड़ के ऋण से जुड़ा है, जिसे बाद में कथित तौर पर ग़लत तरीके से दूसरे खातों और कंपनियों में स्थानांतरित किया गया बताया जा रहा है। एजेंसी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत चार अस्थायी जब्ती आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें रिलायंस समूह से जुड़ी कई कंपनियों की संपत्तियां शामिल हैं। इसमें कुछ विदेशी निवेशों, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और बैंक खातों की जब्ती भी की गई है।

सूत्रों का कहना है कि ईडी को यह संदेह है कि बैंकों से लिए गए कर्ज का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में शेल कंपनियों के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। एजेंसी ने इस संबंध में ब्रिटेन, मॉरीशस और सिंगापुर स्थित कुछ खातों की भी निगरानी शुरू कर दी है। अनिल अंबानी से अगली पूछताछ में एजेंसी यह जानना चाहती है कि उनकी कंपनियों के बीच हुए फंड ट्रांसफर किस उद्देश्य से किए गए, किन लोगों को अधिकृत किया गया था और क्या इन सौदों में किसी विदेशी इकाई की भूमिका रही।

गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को छह महीने की जमानत, पीड़ित पक्ष ने उठाए सवाल ‘बीमारी का बहाना या राहत का रास्ता?’

(जीएनएस)।अहमदाबाद। बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को आखिरकार गुजरात हाईकोर्ट से छह महीने की अंतरिम जमानत मिल गई। अदालत ने यह राहत उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए दी है, लेकिन इस फैसले ने एक बार फिर विवाद को हवा दे दी है। पीड़िता पक्ष ने अदालत में कड़ा विरोध जताते हुए सवाल उठाया कि जब आसाराम विभिन्न शहरों में घूमते रहे और कभी किसी अस्पताल में लंबा इलाज नहीं करवाया, तो अब अचानक गंभीर बीमारी का हवाला क्यों दिया जा रहा है।

गुजरात हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से उनके वकीलों ने जोधपुर कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें पहले भी स्वास्थ्य कारणों से छह महीने की बेल दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि आसाराम की उम्र अब 86 वर्ष हो चुकी है और उन्हें हृदय संबंधी गंभीर बीमारियां हैं, जिनका इलाज जेल में रहकर संभव नहीं है। वकीलों ने यह भी कहा कि यदि आगामी छह महीनों में अपील की सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है, तो वे दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे।

कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि जोधपुर हाईकोर्ट पहले ही चिकित्सा आधार पर उन्हें जमानत दे चुका है, इसलिए गुजरात हाईकोर्ट अलग रुख नहीं अपना सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर राजस्थान सरकार इस जमानत आदेश को चुनौती देती है, तो गुजरात सरकार को भी वैसा करने का पूरा अधिकार रहेगा।

राज्य सरकार की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि अगर जोधपुर जेल में आसाराम को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उन्हें साबरमती जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां आवश्यक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं मौजूद हैं। अदालत ने इस पर सहमति जताई और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आसाराम को साबरमती जेल भेजा जा सकता है।

वहीं, पीड़िता पक्ष के वकील ने अदालत में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आसाराम की तबीयत बिगड़ने की दलीलें पहले भी दी जाती रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे अक्सर विभिन्न शहरों में घूमते देखे गए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि आसाराम जोधपुर, अहमदाबाद, इंदौर और यहां तक कि ऋषिकेश और महाराष्ट्र तक में भी यात्रा करते रहे हैं। ऐसे में यह दावा कि वे इलाज के लिए असमर्थ हैं, न्याय की प्रक्रिया को भटकाने की कोशिश प्रतीत होती है।

उल्लेखनीय है कि आसाराम को 2018 में जोधपुर की पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से वे लगातार जेल में हैं और कई बार स्वास्थ्य कारणों से जमानत की याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। इस बार भी अदालत ने सख्त शर्तों के साथ केवल छह महीने के लिए राहत दी है, जिसके बाद उन्हें या तो वापस जेल लौटना होगा या फिर नई सुनवाई के लिए पुनः याचिका दाखिल करनी होगी।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस अंतरिम जमानत के दौरान आसाराम वास्तव में अपना इलाज करवाते हैं या फिर एक बार फिर ‘बीमारी का हवाला’ अदालतों में सवालों के घेरे में आता है।

पत्नी की जासूसी के लिए GPS ट्रैकर लगाया — सूरत के RTO इंस्पेक्टर पर केस दर्ज, फॉरेस्ट ऑफिसर पत्नी ने खोला राज़

(जीएनएस)।अहमदाबाद। गुजरात में निजता की सीमाएं लांघते एक अजीब और चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। सूरत वन विभाग में कार्यरत एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर महिला ने अपने पति, जो स्वयं सूरत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में इंस्पेक्टर हैं, पर उसकी जासूसी करने और उसके हर कदम पर नज़र रखने के लिए कार में GPS ट्रैकर लगाने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी गई शिकायत में महिला अधिकारी ने बताया कि वह पिछले एक साल से अपने पति से अलग रह रही हैं और इस दौरान उन्होंने अपने माता-पिता के घर पर रहना शुरू कर दिया था। शादी 2020 में हुई थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद दोनों के बीच लगातार मतभेद और झगड़े बढ़ने लगे। आखिरकार वह पति का घर छोड़कर अपने मायके चली गईं। अलगाव का मामला वर्तमान में सूरत जिला अदालत में लंबित है।

महिला ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले जब वह अपनी कार की सफाई करवा रही थीं, तो बोनट के अंदर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाई दिया। गौर से देखने पर पता चला कि यह एक GPS ट्रैकर था, जिसमें सिम कार्ड लगा हुआ था और संभवतः रीयल-टाइम लोकेशन भेजने की क्षमता रखता था। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह किसी सर्विस सेंटर की गलती होगी, लेकिन परिवार के सदस्यों से पूछने पर जब किसी को कुछ नहीं पता चला, तो शक गहराया और उन्होंने सीधे पुलिस से संपर्क किया।

जांच में सामने आया कि यह GPS ट्रैकर उस तरह का डिवाइस था जिसे मोबाइल नेटवर्क से जोड़कर किसी की हर गतिविधि का सटीक पता लगाया जा सकता है। पुलिस को शक है कि आरोपी पति ने यह डिवाइस अपनी पत्नी की लोकेशन जानने और उसके मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए कार में लगाया था।

मेहसाणा जिले में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति द्वारा पूर्व प्रेमिका के घर के बाहर छिपा कैमरा लगाने का मामला सामने आया था, और अब यह घटना सामने आने के बाद एक बार फिर निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सूरत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला अधिकारी की शिकायत के आधार पर आरटीओ इंस्पेक्टर पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78(1)(ii) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी महिला का पीछा करने या उसकी निजता का उल्लंघन करने से संबंधित अपराध है। पुलिस ने आरोपी को बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा है और डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि डिवाइस कब लगाया गया था और किन लोकेशन डेटा को रिकॉर्ड किया गया।

फॉरेस्ट ऑफिसर पत्नी ने कहा, “मैं एक सरकारी अधिकारी हूं। यह मामला केवल एक परिवारिक विवाद नहीं, बल्कि मेरी निजता पर हमला है। अगर कोई सरकारी अधिकारी ही इस तरह की हरकत करेगा तो आम महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा?”

पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने ट्रैकर को किसी ऐप या नेटवर्क सर्वर से जोड़ा था और क्या किसी तीसरे व्यक्ति की इसमें भूमिका रही। इस घटना ने न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर प्रश्न उठाए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि कैसे तकनीक का दुरुपयोग निजी जीवन को निगरानी के दायरे में बदल रहा है।

भारत को चाहिए विश्वस्तरीय बैंक — वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, RBI और बैंकों के साथ चल रही चर्चा

मुं(जीएनएस)।मुंबई। देश की अर्थव्यवस्था को अगले दशक में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक ले जाने की दिशा में सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भारत को अब ऐसे बड़े और विश्वस्तरीय बैंकों की जरूरत है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली में मजबूती से खड़े हो सकें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी बैंकों के साथ विचार-विमर्श जारी है, ताकि भविष्य की बैंकिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ठोस नीति तैयार की जा सके। वित्त मंत्री मुंबई में आयोजित “आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करना” विषय पर 12वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, “भारत की आर्थिक प्रगति और निवेश क्षमता को देखते हुए अब हमें ऐसे बैंकों की आवश्यकता है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर काम करें, बड़े पैमाने पर फाइनेंसिंग कर सकें और विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय वित्तीय संस्थानों की साख बढ़ाएं। हम इस दिशा में आरबीआई और बैंकों के साथ निरंतर संवाद में हैं।” सीतारमण ने कहा कि पिछले दस वर्षों में भारत ने जिस गति से आर्थिक सुधारों को अपनाया है, उसने देश को विकास के एक नए युग में पहुंचा दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रमुख फोकस बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विस्तार और गुणवत्ता सुधार पर है। “पिछले दशक में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में पांच गुना वृद्धि हुई है। हमने सड़कों, रेल, बंदरगाह, रक्षा, डिजिटल नेटवर्क और शहरी विकास में व्यापक निवेश किया है। इसका सीधा असर निजी निवेश पर भी पड़ा है,” उन्होंने कहा।

सोनभद्र में लुटेरी दुल्हन सहित मां और पति गिरफ्तार, नकली शादी कर ठगी का खुलासा

(जीएनएस)।सोनभद्र। म्योरपुर थाना पुलिस ने नकली शादी के नाम पर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियों में लुटेरी दुल्हन रानी कुमारी (23 वर्ष), उसका पति रवि रंजन मौर्य (26 वर्ष) और मां माया देवी (50 वर्ष) शामिल हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह के दो अन्य सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि राजस्थान के जालौर जिले के निवासी रमेश कुमार ने आईजीआईएस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि सोनभद्र के कुछ लोगों ने विवाह कराने के नाम पर धोखाधड़ी की और शादी के तुरंत बाद दुल्हन जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई।

म्योरपुर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। विवेचना में जुटाए गए साक्ष्यों और पीड़ित के बयान के आधार पर टीम ने सक्रिय कार्रवाई करते हुए गुरुवार को तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने अपराध को स्वीकार किया और बताया कि वे संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं।

पुलिस के अनुसार, गिरोह का एक सदस्य कृष्णा मौर्या वर पक्ष से संपर्क कर शादी तय करवाता और मोटी रकम वसूलता था। इसके बाद रानी नकली दुल्हन बनकर जेवरात और नगदी लेकर फरार हो जाती थी। गिरोह मुख्य रूप से दूर राज्यों से आए लोगों को निशाना बनाता था ताकि शिकायत दर्ज कराने में उन्हें दिक्कत हो और गिरोह आसानी से बच निकल सके।

गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि 29 अक्टूबर 2025 को उन्होंने इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान करीब 1.5 लाख रुपये मूल्य के जेवर चोरी किए गए थे, जिन्हें रॉबर्ट्सगंज ले जाने के दौरान पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के अनुसार लूट की बड़ी राशि अभी भी गिरोह के सरगना कृष्णा मौर्या के पास है।

एसपी वर्मा ने बताया कि गिरोह के दो फरार सदस्य — कृष्ण कुमार मौर्य और राजू माली की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और गिरोह के सभी अपराधियों को कानून के कठोर दंड के दायरे में लाया जाएगा।

इस घटना से यह स्पष्ट हुआ है कि नकली शादी के जरिए होने वाली ठगी का मामला लगातार बढ़ रहा है और पुलिस ने इसे रोकने के लिए संगठित कार्रवाई शुरू कर दी है।

क्विकफोस की जहरीली गैस से बना मौत का घर, दो मासूमों ने तड़पकर तोड़ा दम

(जीएनएस)।नई दिल्ली। राजधानी में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया, जब एक मकान मालिक की लापरवाही ने दो मासूम जिंदगियां निगल लीं। गोला का मंदिर इलाके के प्रीतम विहार में चार वर्षीय वैभव और उसकी 16 वर्षीय बहन क्षमा की मौत फास्फीन गैस के जहरीले असर से हो गई। यह गैस उस वक्त फैली जब मकान मालिक श्रीकृष्ण यादव ने गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही कीटनाशक क्विकफोस की 334 गोलियां रख दीं और उनके ऊपर एक लीटर का स्प्रे छिड़क दिया।

जैसे ही गोलियां नमी और तरल के संपर्क में आईं, उन्होंने धीरे-धीरे घुलना शुरू कर दिया और अत्यधिक मात्रा में फास्फीन गैस निकलने लगी। इस गैस ने देखते ही देखते पूरे मकान को एक “गैस चैंबर” में बदल दिया। जहरीली गैस के असर से किराएदार परिवार के सभी सदस्य बीमार पड़ गए। किसी के सीने में जकड़न हुई, किसी को उल्टियां, दस्त और चक्कर आने लगे। गैस ने सीधे उनके नर्वस सिस्टम पर प्रहार किया। अस्पताल ले जाते समय दोनों मासूमों की जान नहीं बच सकी, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज अब भी जारी है।

फास्फीन गैस की मात्रा इतनी अधिक थी कि जब रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना (DRDE) की टीम मौके पर पहुंची और जांच की, तो मीटर पर गैस का स्तर 30 पीपीएम पाया गया—जो मानक स्तर से तीन गुना ज्यादा था। यह स्तर इंसानों के लिए बेहद घातक माना जाता है। टीम ने गैस के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए पूरे छह घंटे तक मेहनत की। घर के भीतर पाउडर और गैस का मिश्रण इतना अधिक था कि सफाई के लिए फायर ब्रिगेड की मदद लेनी पड़ी। पुलिस जांच में सामने आया कि मकान मालिक श्रीकृष्ण यादव ने यह कीटनाशक मेहगांव की एक दुकान से खरीदा था। एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि संबंधित दुकान को तुरंत सील कर दिया गया है, क्योंकि वह बिना सरकारी अनुमति के जहरीले रसायन बेच रही थी। दुकानदार को भी आरोपित बनाया जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, क्विकफोस (एल्यूमिनियम फॉस्फाइड) का इस्तेमाल खेतों और अनाज भंडारण स्थलों पर बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि यह गैस सांस के जरिए शरीर में जाते ही नर्वस सिस्टम, हृदय और फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करती है। बंद कमरों में इसका उपयोग करना आत्मघाती साबित हो सकता है।

यह हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी भी है—कि रसायनों का गलत और लापरवाह इस्तेमाल जीवन की कीमत मांग सकता है। दो मासूमों की यह मौत उस क्रूर सच्चाई को उजागर करती है कि अनजाने में भी की गई एक चूक कैसे घर को गैस चैंबर में बदल सकती है।

कटिहार और सीतामढ़ी में बीजेपी-जदयू नेता चुनावी सभा में गरजे, विपक्ष पर कसा तंज

(जीएनएस)।कटिहार/सीतामढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 नवम्बर को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुवार को कटिहार जिले के बरारी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एनडीए प्रत्याशी विजय सिंह निषाद के समर्थन में जनता का विश्वास जुटाया।

सभा में मुख्यमंत्री सरमा ने कांग्रेस और महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में नरेंद्र मोदी की सोच और नीतीश कुमार के अनुभव की डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के गांव-गांव में विकास की लहर नहीं, बल्कि मोदी-नीतीश की सुनामी बह रही है। जनता अब वादों पर नहीं, काम पर वोट देने को तैयार है।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सरमा ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी ही सेना पर सवाल उठाता है, वह देशभक्ति की उम्मीद नहीं रख सकता। इसके अलावा सरमा ने एसआईआर, राममंदिर, बांग्लादेशी घुसपैठिया और बिहार में जंगलराज जैसे कई मुद्दों को लेकर महागठबंधन नेताओं पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब मानसिक रूप से असंतुलित हो चुके हैं और जनता अब ऐसे नेताओं को जवाब देने के लिए तैयार है।

सरमा ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से गांव-गांव तक विकास पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ शासन चलाया है, वैसा उदाहरण देश में दुर्लभ है।

सभा में एनडीए प्रत्याशी विजय सिंह निषाद ने कहा कि बरारी की जनता का स्नेह उनका सबसे बड़ा बल है और शिक्षा, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में वे बरारी को नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। सभा स्थल पर बड़ी संख्या में जुटी भीड़ “जय मोदी, जय नीतीश” और “विकास ही विकल्प है” के नारों से गूंज उठी। भाजपा, जदयू और लोजपा (रा) के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सरमा ने अंत में जनता से अपील की कि 14 नवंबर को ईवीएम का हर बटन बिहार के भविष्य की दिशा तय करेगा, और राज्य को स्थिर, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए एनडीए प्रत्याशी को समर्थन दें।

इसी बीच सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तीन जनसभाएं आयोजित की। उन्होंने भाजपा और जदयू के उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) तथा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बदला है, जो काम कांग्रेस 65-70 साल में नहीं कर पाई, मोदी ने 11 साल में कर दिया। उन्होंने कहा कि यूपी की तरह बिहार में भी माफिया राज समाप्त होगा और जो खानदानी माफिया हैं, उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।

योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो लोग भगवान श्रीराम और माता जानकी पर सवाल उठाते हैं, उन्हें सबक सिखाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में राजग की सरकार बनने के बाद राज्य में स्थिरता और विकास की नई लहर चलेगी और जनता का जीवन बेहतर होगा।

इस तरह कटिहार और सीतामढ़ी में हुई रैलियों ने एनडीए को चुनावी बढ़त देने की संभावना जताई है और विपक्ष पर तीखी टिप्पणी करके जनता को चुनावी संदेश देने का भी प्रयास किया गया।

जल्द लागू होगी सतत विमानन ईंधन नीति — केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू बोले, किसानों की आय और हरित रोजगार दोनों में होगा इजाफा

(जीएनएस)।नई दिल्ली। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार बहुत जल्द “सतत विमानन ईंधन (Sustainable Aviation Fuel - SAF)” पर राष्ट्रीय नीति लागू करने जा रही है, जिससे न केवल देश का कच्चे तेल पर निर्भरता घटेगी, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि और हरित रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

दिल्ली में आयोजित “भारत सतत विमानन ईंधन शिखर सम्मेलन 2025” को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि “भारत ऐसे चरण में है, जहां विमानन क्षेत्र की तेज़ी से बढ़ती मांग के साथ पर्यावरण संरक्षण की ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। सतत विमानन ईंधन हमें विकास और स्थिरता, दोनों के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा।”

राममोहन नायडू ने कहा कि भारत में सतत विमानन ईंधन का उत्पादन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रतिस्पर्धी दरों पर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि देश में 750 मिलियन टन से अधिक बायोमास और 213 मिलियन टन अधिशेष कृषि अवशेष हर वर्ष उपलब्ध हैं, जिनसे SAF का उत्पादन किया जा सकता है। “यदि हम इस संसाधन का प्रभावी उपयोग करें, तो किसानों की आय में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है,” उन्होंने कहा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस नीति को लागू करने के लिए तेल कंपनियों, निजी निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर रोडमैप तैयार कर रही है। “तेल कंपनियों के अलावा निजी कंपनियों को भी इस क्षेत्र में भाग लेना चाहिए। नवाचार, निवेश और वैश्विक सहयोग के बिना यह पहल सफल नहीं हो सकती,” नायडू ने कहा।

उन्होंने बताया कि SAF के उत्पादन से भारत का कच्चे तेल का आयात बिल प्रति वर्ष 45 से 47 अरब डॉलर तक कम हो सकता है। इसके साथ ही 10 लाख से अधिक हरित रोजगार SAF की पूरी मूल्य श्रृंखला में उत्पन्न होंगे — जिनमें फीडस्टॉक, प्रसंस्करण, आपूर्ति और विमानन ईंधन वितरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

मंत्री ने इस अवसर पर भारत की विमानन क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि “हमारा देश दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ नागरिक उड्डयन बाजार है। भारतीय एयरलाइनों ने अब तक 1,700 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इस विस्तार के साथ हमें ऐसे वैकल्पिक ईंधनों की जरूरत है, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हों बल्कि आर्थिक रूप से भी टिकाऊ साबित हों।” सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक जेट ईंधन में SAF का 1 प्रतिशत मिश्रण, 2028 तक 2 प्रतिशत और 2030 तक 5 प्रतिशत किया जाए। यह ईंधन विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) में ड्रॉप-इन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी मौजूदा इंजनों और बुनियादी ढांचे में बिना बदलाव के इसका प्रयोग संभव होगा।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के अनुसार, 2040 तक वैश्विक SAF की मांग 183 मिलियन टन तक पहुंच सकती है, जबकि वर्तमान में इसका उत्पादन बेहद सीमित है।

मंत्री नायडू ने अपने भाषण के अंत में कहा, “भारत केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक सतत विमानन ईंधन बाजार का निर्माता और नेतृत्वकर्ता बन सकता है। यह नीति हमारे किसानों, उद्योगों और पर्यावरण — तीनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।”

फिजिक्सवाला का 3,480 करोड़ रुपये का आईपीओ 11 नवंबर से, 103–109 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड

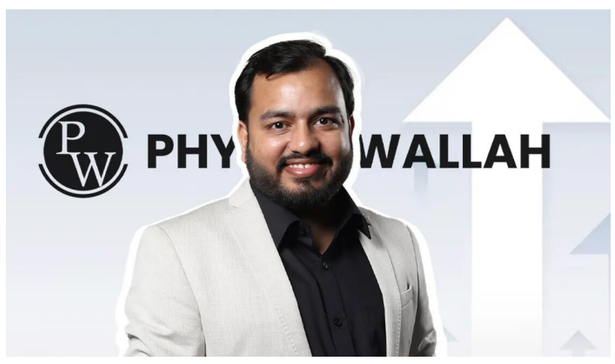

(जीएनएस)।मुंबई। ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर की यूनिकॉर्न कंपनी फिजिक्सवाला ने गुरुवार को अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने प्रत्येक शेयर का प्राइस बैंड 103 से 109 रुपये तय किया है और इस सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से 3,480 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। आईपीओ 11 नवंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और निवेशक 13 नवंबर तक बोली लगा सकते हैं। वहीं, एंकर निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन विंडो 10 नवंबर को खुलेगी। कंपनी का लक्ष्य है कि प्राइस बैंड के अपर साइड पर इस आईपीओ के माध्यम से 31,500 करोड़ रुपये से अधिक का वैल्यूएशन हासिल किया जाए।

आईपीओ दो हिस्सों में बंटी हुई है। इसमें 3,100 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 380 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है। ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर्स अलख पांडे और प्रतीक बूब अपनी-अपनी हिस्सेदारी के रूप में 190-190 करोड़ रुपये की बिक्री करेंगे।

फिजिक्सवाला ने आईपीओ के लिए 137 शेयरों का एक लॉट तय किया है। इसके तहत रिटेल निवेशकों को कम से कम 1 लॉट के लिए सब्सक्राइब करना होगा। कंपनी ने आईपीओ का 75 प्रतिशत हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए रखा है, जबकि 15 प्रतिशत हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए और 10 प्रतिशत हिस्सा रिटेल निवेशकों के रिजर्व किया गया है। आईपीओ से जुटाए गए फंड का उपयोग कंपनी नई ऑफलाइन और हाईब्रिड सेंटर्स के विस्तार, इन सेंटर्स को लीज पर लेने, फिजिक्सवाला की सहायक कंपनी लारलिंग के विस्तार, सर्वर और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा मार्केटिंग गतिविधियों में किया जाएगा। इसके तहत 450 करोड़ रुपये नई सेंटर्स के विस्तार, 548.3 करोड़ रुपये सेंटर्स लीज पर लेने और 47.2 करोड़ रुपये लारलिंग विस्तार में खर्च होंगे।

आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) आज सुबह 9 रुपये पर था। जीएमपी के आधार पर अनुमान है कि आईपीओ की लिस्टिंग अपर प्राइस बैंड 109 रुपये के हिसाब से लगभग 118 रुपये पर हो सकती है, जो कि 8.26 प्रतिशत लिस्टिंग गेन की ओर संकेत करता है। हालांकि, वास्तविक लिस्टिंग कीमत बाजार की मौजूदा स्थिति और मांग-आपूर्ति पर निर्भर करेगी।